

Regarding administration of areas under Schedule V to the Constitution similar to administration of areas under

Schedule VI to the Constitution

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): देश के सभी आदिवासी लोग अपने जल जंगल ज़मीन और खनिज को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनको डर लगने लगा है कि उनके हक छीने जा रहे हैं और साथ ही कुछ राजनैतिक वजह से वे लोग ज्यादा भड़क गए हैं जैसे आरक्षण हो या उनके रोजगार हो या शिक्षा हो। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। उनके पूर्वजों ने इस क्षेत्र को अच्छी तरह से संवार के रखा है। इसलिए मेरा मांग है पांचवी अनुसूची क्षेत्र को छठी अनुसूची के तरह एक अलग से प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर लाना चाहिए ताकि कुछ हद तक अपने आपको शासन करने के साथ-साथ विकास और देश के मुख्यधारा से आदिवासियों को जोड़ने का काम करें साथ ही लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत उनका असेंबली और लेजिस्लेटर बनाने का मांग को भी केंद्र सरकार को पूरा करना चाहिए।